



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ़ 13, 1939

No. 167]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2017

(केस सं. ओ.1/09/2017)

विषय : रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और तुर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सोडियम डाईक्रोमेट” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/4/2017-डीजीएडी.— मैसर्स विष्णु कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे ‘याचिकार्ता’ अथवा ‘आवेदक’ कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और तुर्की (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सोडियम डाईक्रोमेट” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संगत सूचना के साथ एक आवेदन (जिसे आगे याचिका कहा गया है) दाखिल किया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य, घरेलू उद्योग को 'क्षति' तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है, जो एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करते हैं। अतः प्राधिकारी एतद्वारा कथित किसी पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति की एक जांच शुरू करते हैं।

क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम डाईक्रोमेट है जिसे एनहाइड्रस और डाई- हाइड्रेट के रूप में 'सोडियम डाईक्रोमेट' के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम डाईक्रोमेट को कई ऑर्गेनिक सिंथेसिस और दवाओं, विशेषकर इबुप्रोफेन के उत्पादन के लिए आक्सीकारक एजेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसे धातु परिष्करण उद्योगों, जंग रोधी उपयोगों, जल शोधन रसायनों, पिगमेंट और पेंट इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। इसे अन्य क्रोमियम रसायनों के निर्माण में भी उपयोग में लाया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत सीमा शुल्क उप शीर्ष 2841 3000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. घरेलू उद्योग और आधार

5. यह आवेदन भारत में मैसर्स विष्णु कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। दो अन्य घरेलू उत्पादकों अर्थात् मैसर्स श्री कनकदुर्गा क्रोमेट्स (प्रा.) लिमिटेड और मैसर्स कोनार्क क्रोम कैमिकल्स लिमिटेड ने याचिका का समर्थन किया है। देश में विचाराधीन उत्पाद के अन्य आठ उत्पादक हैं, नामतः सिद्धार्थ कैमिकल्स, निफ्टी कैमिकल्स, जियान ब्रदर्स, जीसंस कैमिकल्स, दिव्य ज्योति कैमिकल्स, कर्शन कैमिकल्स, शिवा क्रोम कैमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड और लॉडर्स कैमिकल्स। आवेदक के उत्पादन में भारत में उत्पादित समान उत्पाद के भारतीय उत्पादन का 'एक बड़ा हिस्सा' शामिल है। इसके अलावा, आवेदक ने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातिक से संबद्ध हैं। अतः आवेदक नियम 2 (ख) के तात्पर्य से "घरेलू उद्योग" है और इस प्रकार से कथित नियमावली के नियम 5 (3) के तहत आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ग. समान वस्तु

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। दोनों ही उत्पादों में भौतिक और रसायनिक गुणों, कार्यों व उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमतों, वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसे मापदंडों के सन्दर्भ में तुलनीय गुण हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए इन्हें नियमों के तहत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

घ. शामिल देश और न्यूनतम सीमा

7. वर्तमान जांच में शामिल देश रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और तुर्की हैं (जिन्हें आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है)।

इ. सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वशनीय सूचना उपलब्ध न होने के कारण संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर, डी.जी.सी.आई. एंड एस. से प्राप्त, भारत में आयातों के अनुसार प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों पर विचार करके, आवेदक के खपत मानकों तथा संबंधित संबद्ध देश में प्रचलित विद्युत कीमतों के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

ज. निर्यात कीमत

9. आवेदक द्वारा, प्राप्त सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से भारित औसत आयात कीमत के अनुसार निर्यात कीमत का दावा किया गया है। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, देश के अंदर माल भाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभारों के संबंध में कीमत संबंधी समायोजन का दावा किया गया है।

झ. पाटन मार्जिन

10. कारखाना बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना बाह्य निर्यात कीमत से अधिक है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित की जा रही हैं। पाटन मार्जिन का अनुमान न्यूनतम से अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

11. आवेदक ने निरपेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के रूप में और उत्पादन व खपत, कीमत में कटौती, कीमत अधिक्रमण, कम कीमत पर बिक्री और उसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता, शामिल पूँजी पर प्रतिफल, नकदी प्रवाह, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार अंश के निष्पादन के संबंध में कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। एक पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही 'सामग्री क्षति' के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं।

झ. जांच की शुरुआत

12. प्राधिकारी ने कथित किसी पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य, घरेलू उद्योग को 'क्षति' तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पाया है। तदनुसार प्राधिकारी एतद्वारा

पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति के लिए एक जांच शुरू करते हैं।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

13. जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक (12 माह) है। क्षति अवधि में अपैल, 2013 से मार्च, 2014, अप्रैल 2014 से मार्च 2015, अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 और जांच की अवधि शामिल है।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों में ज्ञात नियांतिकों, भारत में स्थित उसके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001
dgad.india@gov.in

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है (प्राधिकारी की वेबसाइट www.dgtr.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है)।

ठ. समय-सीमा

16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से दिनों 40 तके भीतर वर्तमान मामले में अपने हि (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।
18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या

आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय भाग और अगोपनीय भाग की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जाएँ।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशिकरण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई /सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

३. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

४. असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डा. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**New Delhi, the 4th July, 2017**(Case No - O.I/09/2017)**

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Sodium Dichromate” originating in or exported from Russia, South Africa, Kazakhstan and Turkey.

F. No.6/4/2017-DGAD.— M/s Vishnu Chemicals Limited (hereinafter referred to as ‘petitioner’ or ‘applicant’) has filed an application (also referred to as petition) along with relevant information before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of ‘Sodium Dichromate’ (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Russia, South Africa, Kazakhstan and Turkey (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

A. Product under consideration and like article

3. The product under consideration in the present petition is Sodium Dichromate’ also known as ‘Sodium Dichromate’ in anhydrous and di-hydrate form. Sodium dichromate is used as oxidizing agent for many organic synthesis and bulk drugs especially ibuprofen production. It is used in metal finishing industries, anti-corrosive applications, water treatment chemicals, pigments, paints etc. It is also used in manufacture of other chromium chemicals
4. Product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 2841 3000. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

B. Domestic Industry & Standing

5. The application has been filed by M/s Vishnu Chemicals Limited in India. Two other domestic producers, namely, M/s Sri Kanakadurga Chromates (P) Ltd and M/s Konark Chrome Chemicals Ltd have supported the petition. There are eight other known producers of the product under consideration in the country, namely, Siddhardha Chemicals, Nifty Chemicals, Jian Brothers, Jesons Chemicals, Divya Jyothi Chemicals, Harshon Chemicals, Shiva Chrome Chemicals (P) Ltd and Lords Chemical. The production by the applicant constitutes ‘a major proportion’ of Indian production of the like product produced in India. Further, applicant has neither imported the subject goods, nor are they related to any importer or exporter of the subject goods. The applicant therefore constitutes “domestic industry” within the meaning of Rule 2 (b) and thus satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

C. Like Article

6. The applicant has claimed that there is no known difference in product produced by the applicant and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules.

D. Countries involved and de minimis limits

7. The country involved in the present investigation is Russia, South Africa, Kazakhstan and Turkey (hereinafter referred to as 'Subject Countries').

E. Normal value

8. The applicant has claimed that in absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries, the normal value in the subject countries has been estimated on the basis of best estimates of cost of production in the subject countries, considering major raw materials prices as per imports into India procured from DGCI&S, consumption norms of the applicant, and power prices as prevailing in the respective subject country.

F. Export Price

9. The export price has been claimed by the applicant as the weighted average import price from the subject countries based on the transaction-wise import data procured. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges to arrive at the net export price.

G. Dumping Margin

10. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins estimated are above de minimise.

H. Evidence of Injury and Causal Link

11. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact on profitability, return on capital employed, cash flow, performance on account of capacity utilization, sales and market share of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of 'material injury' being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

I. Initiation of investigation

12. The authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between alleged dumping and injury, to justify initiation of anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, the authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

J. Period of investigation (POI)

13. The period of investigation is April 2016-March 2017 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods April 2013- March 14, April 2014-March 15, April 2015-March 16 and the period of investigation.

K. Submission of Information

14. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street,
New Delhi -110001.
Dgad.india@gov.in

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the authority at www.dgtr.gov.in) within the time limit set out below.

L. Time limit

16. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

M. Submission of Information on Confidential/Non-Confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

24. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DR. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority